



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2007/आषाढ़ 5, 1929

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2007/ASADHA 5, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2007

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन. गण. से सल्फर ब्लैक के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 14/16/2006-डीजीएडी : प्रारम्भिक जांच.— जबकि सल्फर ब्लैक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिन्हें एतदपश्चात् याचिकाकर्ता कहा जाएगा) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सल्फर ब्लैक (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद सल्फर ब्लैक है। सल्फर ब्लैक चमकदार कणों के रूप में उपलब्ध होता है, यह हल्का लाल अथवा हरी आभा लिए हुए पूरी तरह काले रंग का होता है। सल्फर ब्लैक का उपयोग मुख्यतः सेल्यूलोज फाइबर को रंगने के लिए किया जाता है। सल्फर ब्लैक का इस्तेमाल विस्कस स्टेपल फाइबर एवं यार्न को रंगने के लिए भी किया जाता है।

सल्फर ब्लैक के उत्पादन हेतु प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में सल्फर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई-नाइट्रो-क्लोरोबेन्जीन तथा कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है। इस उत्पाद की बिक्री सामान्यतः विभिन्न सांद्रणों में होती है, जो 20% के निम्न स्तर से 100% के उच्च स्तर के बीच हो सकते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय 80% है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सल्फर ब्लैक को अनेक नामों से जाना जाता है। तथापि, इन्हें सामान्यतः बीआर 100, बीआर 200, बीआर 240, इत्यादि नामों से जाना जाता है। बीआर 240 का सान्द्रण 100% होता है। किसी अन्य स्वरूप का सान्द्रण

यथानुपात आधार पर होगा। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उत्पाद का उत्पादन विभिन्न सांद्रणों में किया जाता है तथापि उन्हें एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतः इस जांच में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय -32 के तहत वर्गीकृत सभी सांद्रणों वाले सल्फर ब्लैक को शामिल किया जाएगा। समानताओं की तुलना एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बीआर संख्या द्वारा सूचित विभिन्न सांद्रणों के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

सल्फर ब्लैक को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 32 के उप शीर्ष 320419 तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली के आधार पर) के उप शीर्ष 32041967 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से इस जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

3. घरेलू उद्योग और उसके विचार

याचिका सल्फर ब्लैक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है और याचिका का खुला समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक, भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में सामूहिक रूप से 50% से अधिक हिस्सा रखते हैं। अतः याचिकाकर्ता याचिका दायर कर सकते हैं और नियमों के अर्थ के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग हैं।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिभागी कम्पनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित घरेलू उत्पाद प्रथम दृष्टया चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तु के समान उत्पाद प्रतीत होते हैं।

5. सामान्य मूल्य

नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8 के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी परिकल्पना के मद्देनजर तथा उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा इसका खण्डन किए जाने के अध्यधीन, चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया गया है। तथापि प्राधिकारी उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में उपर्युक्त निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक उपर्युक्त तीसरे देश का चयन कर सकते हैं और यथा समय हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित कर सकते हैं।

6. निर्यात कीमत

संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का अनुमान डीजीसीआई एण्ड एस और अन्य गौण स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, निर्यात के देशों में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों में समायोजन किया गया है।

7. पाटन मार्जिन

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर यह प्रतीत होता है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, भारत को प्राप्त निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। अनुमान लगाया गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा एवं मूल्य तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है। समग्र रूप से और उत्पादों की मांग के संबंध में आयात मात्रा में वृद्धि; बाजार हिस्से में हानि; कीमत कटौती; कीमत हास और मंदी; संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में लाभ प्रदत्ता एवं नकद लाभ में हानि जैसे मानदण्डों से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

9. जांच प्रारंभ

उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं और इसलिए प्राधिकारी, उक्त नियम के नियम 5 के संदर्भ में एतद्वारा कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में एक जांच शुरू करते हैं ताकि किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

10. प्रक्रिया

(क) शामिल देश - वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है;

(ख) जांच की अवधि (पीओआई) - वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01/01/2006 से 31/12/2006 तक की है। तथापि क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2003-2004 से वर्ष 2005-2006 तक की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

(ग) सूचना प्रस्तुत करना: संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए चीन जनवादी गणराज्य की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग

को निर्धारित प्रपत्र एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए लिखा जा रहा है ;

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार
उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110011
संपर्क सूत्र: दूरभाष/फैक्स # 91-11-23061845

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकता है ।

(घ) **समय सीमा:** वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुंच जानी चाहिए । तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिन्हें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर भेजनी होगी । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

(ड.) **अगोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराना:** नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना होगा और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश करना संभव नहीं है तो इसके कारणों संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं ।

(च) **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2007

Initiation

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning import of Sulphur Black from China PR.

F. No. 14/16/2006-DGAD : Initiation.—Whereas Sulphur Black Manufacturers' Association (hereinafter referred to as the Applicants) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred as Rules), alleging dumping of Sulphur Black (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from the China PR, (hereinafter referred to as subject country) and requested for initiation of Anti-Dumping investigations for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. Product under consideration

The product under consideration in the present petition is 'Sulphur Black. Sulphur Black is a Lustrous Grains, imparts full black shade with a slight radish or greenish tone. Sulphur Black is mainly used for dyeing cellulose fiber. Sulphur Black is also useful for dyeing viscose staple fiber and yarn.

Production of Sulphur Black requires sulphur, sodium hydrogen sulfide, di-nitro-chlorobenzene and caustic soda as the major raw material. The product is sold normally in several concentrations, which may vary from as low as 20% to as high as 100%, most popular being 80%. The applicants have contended that Sulphur Black is known by several names. However, normally these are described as BR 100, BR 200, BR 240, etc. BR 240 represents 100% concentration. Any other form would have concentration on pro rata basis. It has been argued that though the product is produced in various concentrations they can be interchangeably used.

Therefore, this investigation would cover Sulphur Black of all concentrations classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act. Specific tariff head at Eight Digit level is 32041967. For the purpose of like to like comparison and dumping margin determination the interested parties would be required to submit information in terms of various concentrations represented by their BR numbers.

Sulphur Black is classified in Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 3204 19 and under subheading 320419 67 under the Indian Trade Classification (Based on Harmonized Commodity Description and Coding system). However, the above classification is indicative only and is no way binding on the scope of this investigation.

2903 5767-2

3. Domestic industry and Standing

The application has been filed by the Sulphur Black Manufacturers' Association and the constituent domestic producers expressly supporting the application collectively account for more than 50% of the total domestic production of the subject goods in India. The applicants, therefore, command the standing for filing the application and constitute the domestic industry for the purpose of this investigation within the meaning of the Rules.

4. Like article

The applicants have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the participating companies and exported from subject countries in terms of essential product properties. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Therefore prima facie, the domestic products manufactured by the domestic industry appear to be like articles to the subject goods imported from China PR.

5. Normal value

In terms of para 8 in Annexure I to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy condition. In view of the above non-market economy presumption, and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal Value of the subject goods in the Peoples Republic of China has been estimated in terms of para 7 of Annexure 1 to the Rules. The Authority may, however, adopt an appropriate third country for the purpose of the above determination in terms of the above provision and notify the interested parties in due course.

6. Export price

The export price of the subject goods exported from the subject country has been estimated on the basis of data collected from DGCI&S and other secondary sources. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation in the Countries of export, port handling and port charges have been made to arrive at the Export Price at ex-factory level.

7. Dumping margin

On the basis of positive evidence placed by the applicants before the Authority it appears that the Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices to India, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

8. Injury and causal link

The applicant domestic industry has furnished information on volume and value of dumped imports from the subject country and various parameters relating to injury to the domestic industry, on account of the product under consideration. Parameters, such as increase in volume of imports, both in absolute terms and in relation to the demand of the products; loss in market share; price undercutting; Price suppression and depression; profitability and cash loss in the manufacturing of subject goods *prima-facie* indicate that the dumped import of the subject goods from the subject country has caused material injury to the Domestic Industry.

9. Initiation

In view of the above the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, and therefore, the Authority, in terms of the Rules 5 of the said Rules, hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

10. Procedure

- a) **Countries involved** The Country involved in the present investigation the **Peoples Republic of China;**
- b) **Period of investigation (POI):** The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is **1.1.2006 to 31.12.2006**. The injury investigation period will however, cover the period 2030-04 to 2005-06 and the POI.
- c) **Submission of information:** The exporters in the subject Country, the government of Peoples Republic of China, through its embassy in India, the importers and users of the subject goods in India and the domestic industry are called upon to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address within the prescribed time limits:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Government of India
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Contact Numbers: Phone/Fax # 91-11-23061845

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

- d) **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Designated Authority at the address mentioned above, not later than **forty (40) days** from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within **(40) forty days** from the date of the letter addressed to them.
- e) **Submission of information on Non-confidential basis:** In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it may deem fit.
- f) **Inspection of public file:** Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7).

R. GOPALAN, Designated Authority